लोक सभा सचिवालय
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध
संसद भवन, नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
Press and Public Relations Wing
Parliament House, New Delhi

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

"व्यवधानों पर रोक लगाने के लिए विधायी निकायों के लिए समान आचार संहिता तैयार की जाएगी" लोक सभा अध्यक्ष

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज संसदीय सौध में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सी.पी.ए) भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति और भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठकों की अध्यक्षता की।

दोनों बैठकों के समाप्त होने के बाद मीडिया के लोगों से बात करते हुए श्री बिरला ने कहा कि भारत में विधायी निकायों के तीस (30) पीठासीन अधिकारियों ने आज की बैठक में विचार-विमर्श किया और इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुईं। श्री बिरला ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारियों की यह आम राय थी कि संसद और राज्य विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह हैं तथा अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर सभा में सार्थक चर्चा और विचार-विमर्श होना चाहिए। श्री बिरला ने यह जानकारी दी कि राज्य विधानमंडलों की बैठकों की सख्या बढ़ाने के साथ-साथ विधायी कार्य की उपयोगिता बढ़ाने को लेकर पीठासीन अधिकारियों के बीच आम राय थी। यह भी महसूस किया गया कि कानूनों को पारित करने के लिए विधानमंडलों में व्यापक और स्वस्थ चर्चा करने की आवश्यकता है और सभा को बिना किसी व्यवधान के अपना कार्य करने की जरूरत है। श्री बिरला ने यह बताया कि पीठासीन अधिकारियों के बीच बनी आम सहमति को देखते हुए, व्यवधानों पर रोक लगाने के लिए विधायी निकायों के लिए समान आचार संहिता बनाई जाएगी। इसके लिए पीठासीन अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी जो विधान सभाओं के अध्यक्षों और विधान परिषदों के सभापतियों के साथ परामर्श करके पीठासीन अधिकारियों के नवंबर 2019 में देहरादून में होने वाले अगले सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह देखते हुए कि इस डिजिटल युग में, जहां डिजिटल दुनिया में नए बदलाव होते रहते हैं, लोक सभा और सभी राज्य विधानमंडलों में 'एक भारत' की संकल्पना के अनुरूप एक जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है, श्री बिरला ने बताया कि सभी पीठासीन अधिकारियों ने सर्वसम्मति से इस बात से सहमति जताई है कि एक समिति इस मुद्दे पर विचार करेगी कि 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)' को राज्य विधानमंडलों में कैसे लागू किया जाए।

यह देखते हुए कि सरकारी धन को समझदारी से और कुशलतापूर्वक खर्च किया जाना चाहिए, श्री बिरला ने यह भी कहा कि राज्य विधानमंडलों की कुशलता को बेहतर बनाने के लिए एक 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' तैयार की जाएगी। श्री बिरला ने यह भी कहा कि पीठासीन अधिकारियों का यह मत है कि बेहतर शोध की मदद

से विधायी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गुणात्मक दृष्टि से बेहतर शोध पत्र सदस्यों को उपलब्ध कराये जाएँ जिससे अपने-अपने सदन में उनके प्रदर्शन में और अधिक सुधार हो।

"A COMMON CODE OF CONDUCT WILL BE FRAMED FOR LEGISLATIVE BODIES TO CHECK INTERRUPTIONS", SAYS LOK SABHA SPEAKER

New Delhi, 28 August 2019: Lok Sabha Speaker Shri Om Birla presided over the meetings of the Executive Committee of Commonwealth Parliamentary Association (CPA) India Region and Presiding Officers of Legislative Bodies in India held in Parliament House Annexe today.

Speaking to the media persons after the conclusion of the two meetings, Shri Birla observed that thirty (30) Presiding Officers of Legislative Bodies in India participated in the deliberations at today's meeting and meaningful discussions on various subjects were held. Shri Birla said that Presiding Officers were of the unanimous view that Parliament and State Legislatures, the representative institutions, are accountable to the people and matters concerning different regions need to be constructively discussed and debated in the House. Shri Birla informed that there was a consensus among the Presiding Officers to increase the number of sittings of the State Legislatures and also to increase the productivity of legislative work. It was also felt that there is a need to have extensive and healthy debates in the Legislatures for passing the laws and the House needs to function without any interruptions. Shri Birla further said that, in tune with the unanimity among Presiding Officers, a common Code of Conduct will be framed for Legislative Bodies to check interruptions. For this, a Committee of Presiding Officers would be formed, which after due consultations with the Speakers of Legislative Assemblies and the Chairmen of Legislative Councils, would present its report at the next Presiding Officers Conference to be held at Dehradun in November 2019.

Observing that in this digital age when new changes keep taking place, the use of technology needs to be uniform in Lok Sabha and all the State Legislatures in sync with the concept of 'Ek Bharat', Shri Birla said that it was unanimously agreed upon by all the Presiding Officers that a Committee would look into the issue how National eVidhan Application (NeVA) would be uniformly applicable in the State Legislatures.

Underlining that public money should be spent judiciously and efficiently, Shri Birla also said that an Action Taken Report would be prepared for improving the efficiency of Legislative Bodies. Shri Birla further said that the Presiding Officers were of the view that the legislative process can be made more efficient with the help of better research and it should be ensured that quality research items are made available to Legislators for better performance in their respective Houses.